भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *300

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का डिजिटलीकरण

***300. डॉ हेमांग जोशीः**

श्री रवींद्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उपयोग, डिजिटल अकाउंटिंग, आपूर्ति शृंखला के डिजिटलीकरण और सरकारी ई-मार्केटप्लेस तथा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में भागीदारी सहित डिजिटल सुविधाओं को कितना अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या डिजिटल और प्लेटफॉर्म-आधारित व्यावसायिक मॉडल अपनाने वाले एमएसएमई के बीच राजस्व वृद्धि, बाजार विस्तार, औपचारिकीकरण और निर्यात भागीदारी के संबंध में कोई स्पष्ट महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *300 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): सरकार उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से मूल्यांकन अध्ययन के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल लेखांकन, आपूर्ति श्रृंखला डिजिटलीकरण और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे प्लेटफार्मों में भागीदारी जैसे पहलुओं को शामिल करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच डिजिटल अंगीकरण की सीमा का समय-समय पर आकलन करती है। नीति आयोग का आउटपुट-आउटकम निगरानी फ्रेमवर्क ऐसी स्कीमों के परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए एक अन्य संस्थागत तंत्र है। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, ओएनडीसी नेटवर्क पर लगभग 2,06,000 व्यापारियों ने कम से कम 1 लेन-देन किया है, लगभग 6 लाख सेवा प्रदाता नेटवर्क पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और इस वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसएमई टीम स्कीम का लाभ उठाते हुए 3127 एमएसएमई ने 01 लाख से अधिक लेन-देन किए हैं।

***